अध्याय 2

Hkkjrh; okfudh vu|la/kku ,o f'k{kk ifj"kn

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के कार्यकलाप निम्नानुसार है :

okfudh vu|la/kku

1- tSofofo/krk ,o tyok;q ifjorZu çHkkx

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. ने जैवविविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक अल्प और दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम शुरू किए है।

d- tSofofo/krk

1 बॉन, जर्मनी में 19 से 30 मई 2008 तक जैविकीय विविधता पर समझौता (सी बी डी) के लिए पार्टियों के सम्मेलन (सी ओ पी–9) की नौवी बैठक सम्पन्न हुई। सी बी डी के लिए सी ओ पी–9 ने विभिन्न विषयों यथा–संरक्षित क्षेत्र, वन जैवविविधता, आक्रामक प्रतिकूल प्रजाति, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन आदि पर 37 निर्णयों को अपनाया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सी बी डी के लिए सी ओ पी–9 की आक्रामक प्रतिकूल प्रजातियों पर निर्णय IX / 4 के अनुसार आक्रामक प्रतिकूल प्रजातियों पर सुझाव देने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को निर्देश दिया। तद्नुसार, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने वन आक्रामक प्रजातियों पर एक संक्षिप्त नोट तैयार किया और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रस्तुत किया।

2 संयुक्त राष्ट्र ने जैवविविधता विषयों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को जैविकीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आई बी डी) के रूप में घोषित किया है। आई बी डी 2009 के लिए विषय था ''जैवविविधता और आक्रामक प्रतिकूल प्रजातियां''। परिषद् के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में 22 मई को जैविकीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस पर आयोजित किए गए समारोहों में परिषद् के क्षेत्रीय संस्थानों के वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, बच्चों, आम लोगों, अधिकारियों ने भाग लिया। जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने आई बी डी के समारोह पर एक विस्तृत रिपोर्ट का संकलन किया और सी बी डी सचिवालय में मसौदा राष्ट्रीय रिपोर्ट में समावेशन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

[k- tyok;q ifjorZu

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाहर से सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं शुरू की हैं :

i. 1995&2007 dh vof/k ds fy, Hkkjr dh ou ensk esa ensk dkcZu LVkWd ,oa xfrdh dk eY;kadu

इस परियोजना के लिए यू एन डी पी–जी ई एफ ने धन दिया है, परियोजना के कार्यकलाप विनरॉक इंटरनेशनल इंडिका के जरिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा परिषद् को दिए गए हैं जो इसकी परियोजना ''यू एन एफ सी सी सी के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय संचार को तैयार करने हेतु कार्यकलाप को समर्थवान बनाना'' के अंतर्गत है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् इस परियोजना का निष्पादन भारतीय सूदूर संवेदी संस्थान (आई आई आर एस), देहरादून के सहयोग से कर रही है। परिषद् का जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, जो परिषद् के क्षेत्रीय संस्थानों और सहभागियों के साथ संचार का केंद्रक बिंदु है, परियोजना से संबंधित सभी कार्यकलापों को कर रहा है।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में देहरादून में 9 और 10 मई 2008 को एस एन सी परियोजना कार्यकलापों की दो

दिवसीय शुरुआती बैठक का आयोजन किया। शुरुआती बैठक में सैम्पलिंग प्लान एवं कार्य पद्धति ब्योरों को अंतिम रूप देने के लिए आई आई आर एस के डीन और वैज्ञानिकों तथा क्षेत्रीय संस्थानों के सभी नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। अध्ययन करने के लिए सैम्पलिंग स्थलों, सैम्पलिंग प्रोटोकॉल और नमूना विश्लेषण के साथ कार्यपद्धति ब्योरे उपलब्ध कराकर एक मैनुअल भी विकसित किया गया।

ii. Hkkjr esa vkorZ lgpjrk vkSj lh Mh ,e {kerk v/;;u dk mi;ksx djds ou dkcZu fofue; dh eki ¼ परियोजना डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट साइंस एंड रीसोर्सेज, यूनिवर्सिटी ऑफ तूसिया (इटली), भारतीय सूदूर संवेदी संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् और उत्तराखण्ड वन विभाग के बीच साझा अध्ययन हैं।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, जो परियोजना के लिए परिषद् का नोडल प्वाइंट है, ने श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में 14 मई 2008 को परियोजना की एक दिवसीय प्रारंभ बैठक का आयोजन किया और परियोजना के तहत जारी कार्यकलापों एवं अब तक की गई प्रगति के बारे में विचार–विमर्श किया गया।

एस०एन०सी० परियोजना की प्रारम्भ बैठक

x- vU; dk;Zdyki

i. cku ¼teZuh½ esa 2 ls 13 twu 2008 rd lEiUu tyok;q ifjorZu ij la;qDr jk"Vª :ijs[kk lEesyu ¼;w ,u ,Q lh lh lh½ dh 28oha ,l ch ,l Vh ,@,l ch vkbZ cSBd esa Hkk-ok-v-f'k-i- çfrfuf/k e.My dh lgHkkfxrk ¼ श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, डॉ. रेनू सिंह, प्रमुख, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, श्री वी.आर.एस. रावत वैज्ञानिक, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग और डॉ. ए. रामचंद्रन, निदेशक, जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन अनुसंधान केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, तमिलनाडु को मिलाकर भा.वा.अ.शि.प. प्रतिनिधि मण्डल ने भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक में भाग लिया।

यू एन एफ सी सी सी की अठ्ठाइसवीं एस बी एस टी ए/एस बी आई बैठक में
भा.वि.अ.शि.प. प्रतिनिधि–मण्डल की सहभागिता

प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों में निर्वनीकरण से उत्सर्जन कम करना : कार्रवाई प्रेरित करने के लिए एप्रोच पर एस बी एस टी ए एजेन्डा मद 5; भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी

पर ए डब्ल्यू जी–के पी एजेन्डा मद 3(बी); अरैर क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.3 और 3.4 के तहत भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी कार्यकलापों के लिए एस बी एस टी ए एजेन्डा मद 8(सी) पद्धति मार्गदर्शन के संबंध में समझौता में पूरी तरह शामिल रहा।

ii. vDdjk tyok;| ifjorlu okrk 21 ls 27 vxLr 2008 rd vDdjk ?kkuk es egkfun'kd] Hkk-ok-v-f'k-i- dh lgHkkfxrk % श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. ने 21 से 27 अगस्त 2008 तक अक्करा जलवायु परिवर्तन बैठक में भाग लिया और अक्करा, घाना में विकासशील देशों में निर्वनीकरण एवं निम्नीकरण से उत्सर्जन कम करना विषय पर प्रस्तुतिकरण किया।

iii. iktuku] iky.M es 1 ls 12 fnlEcj 2008 rd lEiUu ;| ,u ,Q lh lh lh ds fy, ikfV;k dk pkngok lEesyu vkj D;kVk ikVkdky ds fy, ikfV;k dh pkFkh cBd es Hkk-ok-v-f'k-i- ifrfufèk e.My dh lgHkkfxrk % श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. डॉ. रेनू सिंह, प्रमुख, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, श्री वी.आर.एस रावत, वैज्ञानिक डी, जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग और डॉ. ए. रामचंद्रन, निदेशक, जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन अनुसंधान केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, तमिलनाडु को मिलाकर भा.वा.अ.शि.प. प्रतिनिधिमण्डल ने भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के साथ सम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् कार्मिक सम्मेलन के दौरान वानिकी से संबंधित एस बी एस टी ए और ए डब्ल्यू जी–के पी की निम्न एजेन्डा मदों पर समझौतों में शामिल था।

1. एस बी एस टी ए 29 एजेन्डा मद 5 : विकासशील देशों में निर्वनीकरण से उत्सर्जन कम करना: कार्रवाई प्रेरित करने के लिए एप्रोच।
2. ए डब्ल्यू जी–के पी 6 एजेन्डा मद 3(बी) भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी।

भारत ने अपने कथन में आर ई डी डी पर एक गहन एप्रोच का समर्थन किया, जो विश्व स्तर पर निर्वनीकरण से उत्सर्जनों को कम करने में सीधे सहयोग करने वाले देश पार्टियों द्वारा सभी कार्रवाइयों को सम्मिलित करते हैं।

iv. cktby es vrjk"Vh; rduhdh dk;'kkyk es Hkk-ok-v-f'k-i- dh lgHkkfxrk % Mk- jsuw flag] çe[k] tofofoèkrk ,o tyok;| ifjorlu iHkkx] Hkk-ok-v-f'k-i- us lkvk ikoyk] cktby es 4 ls 6 Qjojh 2009 rd **Hkw {k= ifjorlu eY;kdu % वर्तमान परिचालन प्रणाली का अनुभव'' पर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में सूदूर संवेदी आँकड़ों का उपयोग करके भू आवरण एवं भूमि उपयोग परिवर्तन खोज पर विचार–विमर्श किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्बन घनत्व (वन अग्नि सहित वन निम्नीकरण) में और भूमि उपयोग (निर्वनीकरण) में परिवर्तनों के कारण वन भूमि आवरण परिवर्तनों की खोज एवं ट्रैकिंग की वैज्ञानिक रूप से ठोस पद्धतियां और तकनीकों के लिए विशेषज्ञों का विकासशील देशों में सूत्रपात करना है।

साओ पावलो, ब्राजील में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कार्यशाला में डॉ० रेनू सिंह, भा०वा०अ०शि०प० एवं श्रीमती राजश्री रे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहभागिता

v. Jh txnh'k fd'koku] egkfun'kd] Hkk-ok-v-f'k-i- lwjhuke dk nkSjk % श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. को मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल प्लानिंग, लैण्ड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ दी रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम द्वारा 13 मार्च 2009 को पारामारिबो, सूरीनाम में आर ई डी डी समझौता : उच्च वनावरण निम्न निर्वनीकरण देशों का केश ''संगोष्ठी में भाग लेने

और सूरीनाम के वरिष्ठ अधिकारियों एवं समझौताकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया। इसका उद्देश्य एस बी एस टी ए एजेन्डा मद–5 विकासशील देशों में निर्वनीकरण से उत्सर्जन घटानाः कार्रवाई प्रेरित करने के लिए एप्रोच के इतिहास, एस बी एस टी ए और ए डब्ल्यू जी–एल सी ए में तकनीकी, कार्यपद्धति एवं नीति पहलुओं से संबंधित जारी समझौता और यू एन एफ सी सी सी के तहत जारी प्रक्रिया में एच एफ एल डी देशों के लिए सम्भावित रणनीति के साथ सूरीनाम अधिकारियों को संवेदी बनाना है। प्रस्तुतिकरण बहुत पंसद किया गया और इसके बाद गहन प्रश्न–उत्तर सत्र का आयोजन हुआ।

vi teu e; ,u ,Q lh lh dh fo'k"kK cBd e Hkk-ok-v-f'k-lk- dh lgHkkfxrk % श्री वी.आर. एस रावत, वैज्ञानिक–डी, भा.वा.अ.शि.प. ने बॉन, जर्मन में 23 और 24 मार्च 2009 को संदर्भ उत्सर्जन स्तर और संदर्भ स्तर से संबंधित कार्यपद्धति विषयों पर विशेषज्ञ बैठक में भाग लिया।

vii tyok;q U;kt yVj % जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उभर रही घटनाओं और नवीनतम विकासों को शामिल करके नियमित रूप से त्रैमासिक जलवायु न्यूज लैटर तैयार किया, जिसे 2008–09 के दौरान भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट में डाला गया।

?k- çf'k{k.k

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग द्वारा 3 से 7 नवम्बर 2008 तक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून में ''जलवायु परिवर्तन एवं वानिकी सेक्टर के लिए प्रासंगिकता'' पर भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न राज्यों के पच्चीस भारतीय वन सेवा अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के सहभागियों ने अत्यधिक सराहना की है।

भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सहभागी और आयोजक

2- vuqla/kku ;kstuk çHkkx %

अनुसंधान निदेशालय के तहत अनुसंधान योजना प्रभाग आधारिक, पारदर्शी एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाकर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा निधीयित नए अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की योजना, प्रक्रमण एवं निष्पादन का काम करता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान इस प्रकार निम्न उपलब्धियां हासिल की गई:

- vu|l/kku ;kstuk çHkkx ने नीचे उल्लिखित तिथियों पर संस्थान स्तर पर अनुसंधान सलाहकार समूह बैठकों का समन्वयन किया।

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	–	28–29 अगस्त 2008
उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	–	04–05 सितम्बर 2008
वन उत्पादकता संस्थान, रांची	–	23–24 सितम्बर 2008
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	–	29–30 सितम्बर 2008
काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूरू	–	13–14 अक्टूबर 2008
हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	–	23–24 अक्टूबर 2008
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	–	14–15 नवम्बर 2008
वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	–	17–18 नवम्बर 2008

इस साल राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षकों, विभिन्न स्तरों के वैज्ञानिकों, वन अधिकारियों, विविध पणधारियों यथा–गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों प्रगतिशील किसानों और विश्वविद्यालयों को शामिल करके अनुसंधान सलाहकार, समूहों को ज्यादा विस्तृत बनाया गया है। वर्ष 2008–09 से पियर ग्रूप टिप्पणियां लेने की शुरूआत भी की गई और तदनुसार उपभोक्ता उद्यानों की आवश्यकता के अनुरूप परियोजनाओं को संशोधित किया गया।

- vu|l/kku uhfr lfefr cBd ½ अनुसंधान सलाहकार समूह द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को अनुसंधान नीति समिति के समक्ष रखा गया, जिसे श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में 11 से 13 फरवरी 2009 को आयोजित किया गया था ताकि परिषद् के अधीन आठ अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नए अनुसंधान प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृत दी जा सके।

दसवीं अनुसंधान नीति समिति की बैठक के दौरान, अनुसंधान नीति समिति (आर पी सी) सदस्यों द्वारा नयी परियोजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें से भा.वा.अ.शि.प. निधीयन, रूपये 810.3 लाख के लिए इक्यासी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। दो परियोजनाओं को बाह्य निधीयन के लिए स्वीकृत किया गया और छः परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया गया। दो अखिल भारतीय परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। नयी अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की संस्थानवार स्वीकृति का सार नीचे दिए अनुसार है।

nloh vkj ih lh e ubl ifj;kstukvk dh Lohdfr;k dk lkj ½

lLFkku dk uke	ifj;kstukvk dh l[;k	Lohdr dy jkf'k ¼yk[k½
हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	2	55.85
वन उत्पादकता संस्थान, रांची	7	84.63
उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	3	32.85
काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूरू	17	107.33
वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	14	143.536
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	23	200.503
वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान,		
कोयम्बटूर	12	146.18
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	3	39.51
;kx	81	810-389

अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं को सिद्धांतः स्वीकृत किया गया और अध्यक्ष ने इच्छा जाहिर की कि अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के विभिन्न घटकों को दाता एजेन्सियों को उनकी आवश्यकता एवं फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। संस्थानों के निदेशकों से निवेदन किया गया कि वे परिषद् के साथ परामर्श करके अपने–अपने स्तर पर बाह्य निधीयन के लिए मामले को उठाएं।

fun'kdk dh cBd

18 सितम्बर 2008 को श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिसर मुख्यालय के प्रमण्डल कक्ष में तीसरी निदेशकों की बैठक का आयोजन किया गया। निदेशकों की बैठक का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए किया गया, जिसके लिए संस्थानों के निदेशकों के साथ परामर्श करके विभिन्न निदेशालयों द्वारा कार्यसूची निर्धारित की गई। परिचर्चा किए गए कुछ विषय, आर ए जी में संबंधित राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य अनुसंधान प्रतिनिधियों को बुलाकर, अनुसंधान परियोजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन, अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के स्तर एवं शोध परियोजनाओं की बाह्य निधीयन की आवश्यकता से, संस्थानों एवं राज्यों के बीच के अंतर को भर रहे है।

ckl rduhdh lgk;rk leg ¼ch Vh ,l th½ &Hkkjrh; okfudh vuqla/kku ,oa f'k{kk ifj"kn] ngjknu

जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार द्वारा बी टी एस जी–आई सी एफ आर ई, देहरादून का गठन किया गया। भा.वा.अ.शि.प. के बी टी एस जी द्वारा निम्न कार्य शुरू किए गए।

vk;kftr izf'k{k.k%

1. पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण : सामाजिक वानिकी एवं पारि–पुनर्स्थापन केंद्र, इलाहाबाद द्वारा आयोजित 13–17 अक्टूबर 2008।
2. हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण : हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा आयोजित 13–17 अक्टूबर 2008।
3. राजस्थान के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण : शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा आयोजित 4–8 नवम्बर 2008।
4. गुजरात के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण : शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा आयोजित, 12–16 नवम्बर 2008।
5. गुजरात के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण : उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा आयोजित 13–17 अक्टूबर 2008।

ckal lkfgR; dk eqæ.k%

वन कार्मिकों, किसानों एवं क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए ''बांस रोपण एवं उपयोगिता'' पर हिन्दी पुस्तक की 5000 प्रतियां प्रकाशित की गई। बी टी एस जी–आई सी एफ आर ई के तहत राज्य बांस मिशन, प्रशिक्षणों का आयोजन करने वाले संस्थान, सहोदर संगठन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में इसका निःशुल्क वितरण किया गया।

varjk"Vªh;@jk"Vªh; lsfeukjksa dk vk;kstu%

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा 17–19 मार्च 2009 तक ''बांस रोपण, प्रबंध और इसके उपयोग'' पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

iapo"khZ; iqujh{k.k

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट; वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर और वन अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद की पंचवर्षीय पुनरीक्षण टीमों ने अपना पुनरीक्षण कार्य पूरा

कर लिया है और अपनी–अपनी संबंधित पंचवर्षीय पुनरीक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत कर दिया है। निदेशक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की पंचवर्षीय रिपोर्ट लगभग पूरी हो रही है।

3- vuqoh{k.k ,oa ewY;kadu izHkkx

अनुसंधान निदेशालय के तहत अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग परिषद् संस्थानों की जारी सभी अनुसंधान परियोजनाओं का पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन करता है। यह प्रभाग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपायों एवं पूर्णता के साथ उद्देश्यों की उपलब्धियां हासिल करने का सुझाव देता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान, परिषद् के सभी संस्थानों की 380 जारी अनुसंधान परियोजनाओं (भा.वा.अ.शि.प. निधीयित–225 और 125 बाहर से सहायता प्राप्त) का पुनरीक्षण/मूल्यांकन किया गया। उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों/एजेन्सियों के माध्यम से 20 अनुसंधान परियोजनाओं (पूर्ण/जारी) का स्वतंत्र पुनरीक्षण भी किया गया।

अनुसंधान निदेशालय का यह प्रभाग परिषद् की समेकित वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने के लिए संस्थानों से सालाना कार्य योजना पर सूचना भी एकत्र करता है।

4- ifj;kstuk lw=hdj.k çHkkx

यह प्रभाग पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं के सूत्रीकरण और निधीयन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों को उनकी निधीयन आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए परिषद् संस्थानों/केंद्रों एवं सक्षम दाता एजेन्सियों के बीच संयोजक के रूप में काम करता है। यह परिषद् संस्थानों/केंद्रों के लिए निधियों को अवमुक्त करने का समन्वयन और पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में इनकी उपयुक्तता के संबंध में परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन भी करता है।

ckgj ls fu/khf;r ifj;kstuk,a %

प्रभाग परियोजना निधीयन के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों के साथ सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों द्वारा निधीयित 146 परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों द्वारा निधीयित 6 परियोजनाओं का कार्यान्वयन परिषद् के आठ संस्थानों और तीन केंद्रों में किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों द्वारा निधीयन के लिए क्रमशः 76 परियोजनाएं और 4 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

मुख्य दाता एजेन्सियां हैः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, बांस उपयोग का राष्ट्रीय मिशन।

मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियां हैः जापान इंटरनेशनल को–आपरेशन एजेन्सी, स्वीडिश इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी, इंटरनेशनल फाउन्डेशन फॉर साइंस, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर और डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट।

प्रभाग पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में दाता एजेन्सियों की निधीयन आवश्यकताओं और मार्गदर्शन के अनुसार परिषद् संस्थानों के अनेक परियोजना प्रस्तावों के सूत्रीकरण का समन्वयन करता है और उपयुक्त प्रस्तावों को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों को उनकी स्वीकृति एवं प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रमित करता है, उदा. – यूकेलिप्टस गाल वाष्प पर वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना : पॉपलर पर व.अ.सं., देहरादून की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना; जट्रोफा पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना।

सहयोगी प्रक्षेपित परियोजनाओं/परिषद् संस्थानों/केंद्रों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनेक समझौता पत्रों एवं समझौतों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए संवीक्षित एवं प्रक्रमित किया गया।

fcgkj ifj;kstuk

प्रभाग ने ''बिहार राज्य में समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना'' शीर्षक से गहन बिहार परियोजना के निष्पादन का समन्वयन किया (फेज–I), इसे बिहार राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ परिषद् द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्तरी बिहार के वैशाली जिले में किसानों के खेतों में पॉपलर आधारित कृषि वानिकी कार्यक्रम पर भा.वा.अ.शि.प. घटक से संबंधित कार्यकलापों का क्षेत्र भ्रमण द्वारा अनुवीक्षण किया गया। वीडियो कांफ्रेन्सिंग के द्वारा पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन भी किया गया और इससे परियोजना के सतत अनुवीक्षण में सहायता मिली।

Hkkjr dk ouksa dk bfrgkl&1947 dk ckn

ई पी स्टेविंग द्वारा 4 खण्ड़ों में लिखी पुस्तक ''दी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया'' के अनुक्रम में जो 1796 से 1947 तक भारत में वन विकास का कालानुक्रम देती है, यह निर्णय लिया गया कि 1947 से 2005 तक परवर्ती अवधि के लिए भारत में वनों के इतिहास को प्रलेखित किया जाए और यह काम भा.वा.अ.शि.प. को सौंपा गया है। विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद इस पुस्तक के अध्यायों को अंतिम रूप दिया गया जिसमें शामिल हैं वन नीति, वन अधिनियम और कानून, वन प्रशासन, वन प्रबंध, वन्यजीव प्रबंध, पंचवर्षीय योजना के तहत वानिकी, सामाजिक वानिकी, सहभागी वन प्रबंध और राजस्व प्राप्ति आदि।

ग्यारह अध्यायों को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रस्तावित पुस्तक का पहला भाग ''पोस्ट इंडीपेंडेन्स डवलपमेंट इन इंडियन फॉरेस्ट्री, वॉल्यूम I'' शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

okfudh f'k{kk

5- f'k{kk çHkkx

देश में वानिकी शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी गई ताकि, वानिकी संकायों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सशक्त बनाया जा सके जैसे अवसंरचनात्मक विकास, वैज्ञानिक उपकरणों, पुस्तकों, जर्नलें की खरीद, धूमिका कक्ष बनाना और शिक्षण मैनुअलों में इसी प्रकार अन्य शिक्षण/शोध सुविधाएं, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन, कार्यशालाओं/सेमिनारों में शिक्षकों की भागीदारी तथा विद्यार्थियों के अध्ययन दौरे। नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 में अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक 14 विश्वविद्यालयों को कुल रूपये 502.71 लाख का अनुदान दिया गया :

Ø-l-	fo'ofo|ky; dk uke	tkjh jkf'k ¼:-yk[k e½
1	डॉ. व्हाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	7.35
2	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	27.50
3	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर	3.00
4	वन अनुसंधान संस्थान, सम विश्वविद्यालय, देहरादून	172.70
5	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	6.75
6	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	49.00
7	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	23.00
8	डॉ. बी.एस.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डापोली	10.21
9	पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	2.00
10	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	7.00
11	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	39.70
12	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , झालावाड़ (राजस्थान)	51.50
13	इलाहाबाद कृषि संस्थान सम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	38.00
14	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी (गुजरात)	65.00
	;kx	502-71 yk[k

Lukrd@LukrdkŸkj ikB~;Øeksa dk fy, okfudh ikB~;Øe dk ekudhdj.k ,oa ,dhdj.k %

इस निदेशालय ने विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे बी एस सी/एम एस सी (वानिकी) पाठ्यक्रमों के मानकीकरण एवं एकीकरण से संबंधित कार्य किया है ताकि सामान्यतः अलग–अलग समुदायों और विशेषकर वानिकी सेक्टर के हितों को सुरक्षित करने हेतु गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

okfudh egkfo|ky;@fo"o; ikB~;Øe dk iR;k;u %

विषय पाठ्यक्रम एवं इसे प्रदान करने वाले वानिकी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को मान्य करने के लिए, ए आई सी टी ई के पैटर्न पर प्रत्यायन की प्रक्रिया शुरू की गई और इस प्रभाग द्वारा वानिकी पाठ्यक्रमों को प्रत्यासित किया जा रहा है। केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर (केरल) के वानिकी पाठ्यक्रमों को वर्ष 2008–09 में इस निदेशालय द्वारा मान्य किया गया और अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने वानिकी पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए निवेदन किया है जो इस निदेशालय में प्रक्रिया के तहत हैं।

çf'k{k.k %

शिक्षा निदेशालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् अधिकारियों/वैज्ञानिकों के, देश के भीतर और विदेश में विभिन्न पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी जानकारी/दक्षताओं का उच्चीकरण करने के लिए, प्रतिनियुक्ति के मामले भी देखता है। जो इस प्रकार है :

1. 57 वन अधिकारियों/वैज्ञानिकों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए परिषद् से नियुक्त किया गया अथवा अनुमति प्रदान की गई।
2. 162 वन अधिकारियों/वैज्ञानिकों को देश के भीतर राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए परिषद् से नियुक्त किया गया अथवा अनुमति प्रदान की गई।

vuqla/kku lgk;rk ç.kkyh %

परिषद् के वैज्ञानिकों को अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराने के लिए परिषद् और इसके संस्थानों द्वारा साक्षात्कार लेकर विभिन्न जे आर एफ/एस आर एफ/आर ए की नियुक्ति की गई जिसके लिए इस निदेशालय ने परिषद् और इसके संस्थानों में चलाई जा रही अहम् परियोजनाओं में काम करने के लिए जे आर एफ/एस आर एफ/आर ए के चयन हेतु चयन समितियां गठित करने/स्वीकृति में अहम भूमिका अदा की है।

ekuo lalk/ku fodkl dk;Øe

चूंकि इस निदेशालय में प्रबंधकीय संवर्ग, वैज्ञानिक संवर्ग और तकनीकी संवर्ग के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक मानव संसाधन विकास (एच आर डी) प्रकोष्ठ भी है, जिसके लिए इस निदेशालय ने विभिन्न विषयों में 7 प्रशिक्षणों का आयोजन किया। वर्ष 2008–09 में परिषद् के 142 अधिकारियों/वैज्ञानिकों को इनके ज्ञान/दक्षता निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया गया।

6- uhfr vuqla/kku çHkkx

1. शिक्षा निदेशालय को वानिकी के क्षेत्र में ''नीति अनुसंधान'' कार्यों को करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निम्न विषयों पर कार्य लगातार जारी है :

- देश में वन और वृक्षावरण के अनुपात के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक आधार।
- गरीबी उन्मूलन की राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए वानिकी के सहानुबंध का विश्लेषण करना, इस प्रकार नीति निर्धारण को राष्ट्रीय विकास परिदृश्य के लक्ष्यों/उद्देश्यों के अनुरूप लाना।

- क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तरों पर रोपण कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए वृक्ष सुधार हेतु गुणवत्ता बीजों/रोपण स्टॉक के नियंत्रण एवं विपणन के लिए प्रमाणीकरण क्रियाविधि पर नीति एवं विधायी उपायों का सूत्रीकरण।
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के साथ संबंधित सेक्टरों की नीतियों में असंगति की पहचान के लिए डेस्क पुनरीक्षण और असंगति के समाधान के लिए सुझाव।

2. नीति अनुसंधान अध्ययन करने के लिए, निम्न परामर्शदाताओं को कार्य सौंपा गया :

- एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट एंड एंवायरमेंट साइंस, देहरादून
- टी एन एस–इंडिया प्राइवेट लि. नई दिल्ली
- श्री प्यारे लाल एंड अदर्स, फगवाड़ा (पंजाब)

3. कंसल्टेन्सी ''वन बीज एवं वनस्पति मूल के रोपण स्टॉक के प्रमाणीकरण के लिए संस्थात्मक एवं विनियामक क्रियाविधि की आवश्यकता'' को 2008–09 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

vkink çca/ku %

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने परामर्श, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया है ताकि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में वन पारितंत्र की भूमिका और इस प्रकार की खतरनाक घटनाओं के सुधारात्मक प्रभावों को सभी स्तरों पर पूरी तरह से समझा जा सके। परिषद् और इसके संस्थानों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर संस्थानों/संगठनों के साथ नेटवर्क भी किया जाएगा ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तरों पर योजना उपायों पर केंद्रित परामर्शों के आवश्यक भाग बने रहें।

okfudh foLrkj

7- ehfM;k ,oa çdk'ku çHkkx

मीडिया एवं प्रकाशन प्रभाग, विस्तार निदेशालय वानिकी सेक्टर में अनुसंधान परिणामों के प्रसार के लिए परिषद् के संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों एवं विस्तार कार्यकलापों को देखता है। प्रभाग परिषद् संस्थानों के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के मासिक विवरण का पोषण करता है और इनसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अवगत कराता है। प्रभाग परिषद् का त्रैमासिक न्यूजलैटर (जो परिषद् संस्थानों द्वारा की गई नवीनतम महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रकाशित करता है) और परिषद् विवरणिकाओं ब्राशुअर्स का प्रकाशन करता है। परिषद् और इसके संस्थानों की रिपोर्टों को एकत्रित, संकलित, संपादित करके परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है।

राज्य वन विभागों के सहयोग से वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना और परिषद् संस्थानों द्वारा अपनाने के लिए प्रदर्शन गांवों के चयन पर कार्य में काफी प्रगति हुई है। अलग–अलग राज्यों में 22 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। देश के विभिन्न पारि–जलवायवीय क्षेत्रों में 8 प्रदर्शन गांवों की स्थापना की गई।

okfudh vuqla/kku esa foLrkj j.kuhfr;k ij jk"Vªh; dk;Z'kkyk

विस्तार निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून ने परिषद् के लिए वानिकी अनुसंधान में विस्तार रणनीतियां विकसित करने के लिए देहरादून में 15 और 16 जनवरी 2009 को ''वानिकी अनुसंधान में विस्तार रणनीतियां''पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री जगदीश किशवान, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून ने किया। पदम भूषण श्री चण्डी प्रसाद भट्ट, प्रख्यात पर्यावरणविद् इस अवसर पर माननीय अतिथि थे।

''वानिकी अनुसंधान में विस्तार रणनीतियां'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

डॉ. रवीन्द्र कुमार, उपमहानिदेशक (विस्तार), भा.वा.अ.शि.प. ने माननीय अतिथियों एवं देशभर से आए सहभागियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि, श्री जगदीश किशवान ने अपने मुख्य संबोधन में सूचित किया कि परिषद् राज्य वन विभागों के सक्रिय सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों में 22 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने में सफल रही है।

पूर्ण सत्र प्रगति पर

पदम भूषण श्री चण्डी प्रसाद भट्ट ने उपस्थिति लोगों के साथ अपने अनुभवों को बांटा। उन्होंने जोर दिया कि अनुसंधान आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय करते समय महिलाओं की प्राथमिकताओं पर विचार करना आवश्यक है। उन्होने वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना पर अपनी खुशी जाहिर की है।

8- lkf[;dh çHkkx

सांख्यिकी प्रभाग द्वारा 2008–09 में निम्न कार्य किए गए :

- भा.वा.अ.शि.प.–आई टी टी ओ परियोजना को जुलाई 2009 तक बढ़ाया गया। इस परियोजना के तहत् परिषद् के पांच संस्थानों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर; वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून और वन उत्पादकता संस्थान, रांची में पांच क्षमता निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न हुए। परिषद् संस्थानों के नोडल अधिकारियों (सांख्यिकी) को नए फॉर्मेटों एवं मैनुअल के बारे में बताया गया।
- टिम्बर/बैम्बू ट्रेड बुलेटिन के चार अंको को संकलित एवं प्रकाशित किया।
- फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इंडिया के 2005 अंक को संकलित, वैधीकृत और संवीक्षा की गई। स्वीकृत एवं प्रकाशन हेतु अंतिम प्रति तैयार की गई।

आई टी टी ओ कार्यशाला प्रगति पर

9- Ik;koj.kh; çHkko eY;kdu çHkkx

विस्तार निदेशालय के तहत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग प्रमुख परियोजना प्रस्तावकों में वैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे–जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप ऑफ कम्पनीज, सिंगेरनी कोलेरीज कम्पनी लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट लि., नई दिल्ली नगर परिषद्, हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि., राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, चण्डीगढ़ प्रशासन, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड, रायपुर, रिलायंस इंडिया लि., राष्ट्रीय जलविद्युत निगम, आंध्र प्रदेश, पर्यटन विकास निगम, आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लि., राष्ट्रीय वनीकरण पारि–विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एस्सर ग्लोबल लि.। यह प्रभाग विकास हस्तक्षेपों का सामना कर रहे विभिन्न पारितंत्रों के पोषणीय प्रबंध के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा हासिल करने हेतु सर्वोत्तम पद्धतियां विकसित करने के लिए अन्य संस्थानों से देशभर के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से परिषद् संस्थानों के वैज्ञानिकों के विशेषज्ञता के एक पूल के रूप में कार्य करता है।

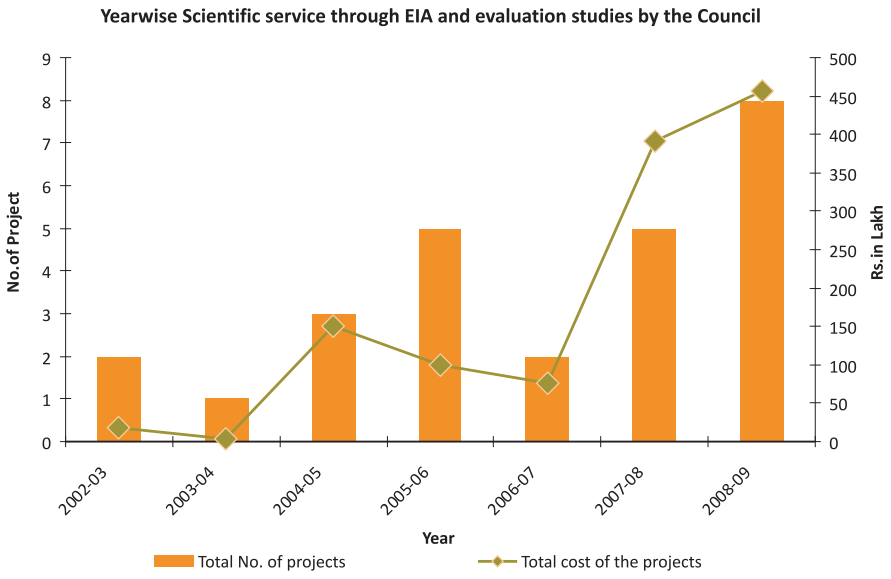

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान निम्न अध्ययन शुरू किए गए:

1. हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड, शिमला द्वारा प्रदत्त एकीकृत काशांग जलविद्युत परियोजना (243 मे.वा.), हिमाचल प्रदेश के लिए ई आई ए एवं ई एम पी तैयार करना।

2. जे एस डब्ल्यू एनर्जी लि., मुम्बई द्वारा प्रदत्त कुथेर जल विद्युत परियोजना (के एच ई पी) (260 मे.वा.) चम्बा, जिला हिमाचल प्रदेश के लिए ई आई ए और ई एम पी रिपोर्ट तैयार करना।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उत्तरकाशी जिला, उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निर्मित किए जाने वाले लोहारिनाग पाला जल विद्युत परियोजना (4X150 मे.वा.) के जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का मूल्यांकन।

4. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड, रायपुर द्वारा दिए गए बोधघाट जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना और उप–योजना तैयार करना।

5. टिहरी जल विद्युत विकास निगम, ऋषिकेश द्वारा दी गई नहर भाग के लिए भारत में और जलाशय भाग (4060 मे.वा.) के लिए भूटान में संकोश बहुउद्देशीय परियोजना के डी पी आर अद्यतन के लिए एक मौसमी आँकड़ों के साथ त्वरित ई आई ए और ई एम पी।

6. टिहरी जल विद्युत विकास निगम, ऋषिकेश द्वारा दी गई जधगंगा (50 मे.वा.) और कारमोली (140मे.वा) परियोजना के डी पी आर अद्यतन के लिए एक मौसमी आँकड़ों के साथ त्वरित ई आई ए और ई एम पी।

7. एस्सार पावर लिमिटेड, झारखण्ड द्वारा प्रदत्त झारखण्ड में 2000 मे.वा. पिट हैड थर्मल पावर स्टेशन के लिए जैवविविधता मूल्यांकन रिपोर्ट।

8. टिहरी जल विद्युत विकास निगम, ऋषिकेश द्वारा प्रदत्त बुनाका हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (180 मे.वा.) भूटान के डी पी आर अद्यतन के लिए एक मौसमी आँकड़ों के साथ त्वरित ई आर ए और ई एम पी।

फोनिक्स रूपिकोला–जलमग्न क्षेत्र से अभिलिखित एक दुर्लभ पादप

संकोस नदी–प्रस्तावित बांध स्थल

iz'kklu funs'kky;

10- lwpuk izk|kfxdh izHkkx

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्रशासन निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प. में और इसके संस्थानों/केंद्रों में उपभोक्ताओं की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिषद् में ई–गवर्नेन्स कार्यकलापों का एक भाग होने के नाते सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं के द्वारा ई–गवर्नेन्स सूत्रपात में अग्रता हासिल कर ली है, जिन्हें कार्यान्वित किया गया है अथवा कार्यान्वयन के तहत् हैं।

bZ&xousZUl

गहन उद्यम स्तर सॉफ्टवेयर समाधान यथा–भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना प्रणाली (आई एफ आर आई एस) की योजना के द्वारा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्र और वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए भावी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सूत्रपातों के आधार पर अब भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का नाम ई–गवर्नेन्स का पर्याय बन गया है।

Hkkjrh; okfudh vuqla/kku lwpuk iz.kkyh ¼vkbZ ,Q vkj vkbZ ,l½

भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना प्रणाली का उद्देश्य वर्तमान हाथ से काम करने की प्रक्रिया (मैनुअल) को एक स्वचालित प्रणाली में हस्तांतरित करना, कार्य प्रवाह स्वचालन एवं जानकारी प्रबंध के माध्यम से अनुक्रियाशीलता बढ़ाना, अनुसंधान परियोजनाओं का वास्तविक समय सूचना प्रबंध, सूचना एवं सेवाओं की पहुंच में पणधारियों, उपभोक्ताओं की सुविधा, बाह्य पणधारियों के साथ परिषद् के जुड़ाव का अनुवीक्षण करना है। आई एफ आर आई एस की सफलता को ध्यान में रखते हुए अनेक राष्ट्रीय एजेन्सियां इसका उपयोग ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम के अधिष्ठापन के लिए एक कार्ययोजना के रूप में कर रहे हैं और अपने यहां योग्यता पूल बनाने के लिए परिषद् से संपर्क कर रहे हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना प्रणाली दो मुख्य भागों को मिलाकर है उदाहरणार्थ :

- भारतीय वानिकी अनुसंधान प्रबंध सूचना प्रणाली और
- भारतीय वानिकी अनुसंधान प्रशासन सूचना प्रणाली

उद्यम स्तर यथा–परिषद् और इसके क्षेत्रीय संस्थान एवं केंद्रों पर सभी मुख्य अनुसंधान और जारी अनुसंधान सेवा क्षेत्रों को शामिल करके।

भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना प्रणाली का विकास तीन अवस्थाओं के द्वारा नियोजित किया गया उदाहरणार्थ :

voLFkk I: प्रत्ययीकरण (6 और 7 जनवरी) जिसमें प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं आई टी अवसंरचना आवश्यकताओं, सेवाओं की प्रक्रिया पुनर् अभियांत्रिकी और कार्यात्मक संरचना पर विस्तृत अध्ययन किया गया।

voLFkk II: परियोजना विकास (07 मार्च से 07 अगस्त) जिसमें मैसर्स विप्रो, गुड़गाँव को परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया और सक्षम सुधार क्षेत्र की पहचान की गई और विस्तृत कार्यात्मक एवं तकनीकी संरचना के साथ भा.वा.अ.शि.प. के लिए विश्लेषण रिपोर्ट ''एज इज'' रिपोर्ट एवं ''टू–बी'' प्रक्रियाएं तैयार की गई। प्रणाली विकासकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन को भी अंतिम रूप दिया गया और अंत में

voLFkk III: सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्वयन (08 जनवरी से 09 मार्च) जिसके तहत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और जो कार्यान्वयन के तहत् है।

परियोजना संस्थागत रूपरेखा ने एक प्रभावी भूमिका अदा की है। जिसमें पणधारियों की आकांक्षाओं और चिंताओं

को उजागर करने के लिए चार परिषद् शीर्ष समिति बैठक और करीब 50 अन्य संस्थान शीर्ष एवं तकनीकी समिति बैठकों का आयोजन किया गया। ई–चैम्पियन (परिवर्तित एजेन्ट) के चार गहन प्रशिक्षणों और देहरादून, बंगलूरू, शिमला में नए आई आर आई एस अनुप्रयोग में धीरे–धीरे अनावरण और जोरहाट में प्री–गो–लाइव प्रशिक्षण तथा बाह्य अतिथियों के व्याख्यानों के द्वारा भी परिवर्तित प्रबंधन लाया गया। इन प्रशिक्षणों के दौरान स्थानीय संस्थानों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया ताकि उन्हें नए विकसित उपयोगों की जानकारी से अवगत कराया जा सके।

ई–चैम्पियन प्रशिक्षण के अलावा, संस्थान स्तर पर कई दौर के प्रशिक्षण और उपभोक्ता स्वीकार्यता प्रशिक्षण भी किए गए ताकि अनुप्रयोग की स्वीकार्यता को बढ़ाया जा सके।

यह योजना बनाई गई कि भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना प्रणाली को पहली अवस्था में चार आधारभूत मापांकों के साथ संवृद्धि के रूप में उपयोग किया जाएगा, उदाहरणार्थ : अनुसंधान सूचना प्रणाली, कार्मिक सूचना प्रबंध प्रणाली, पेरोल प्रबंध प्रणाली और वित्तीय लेखा प्रणाली, जो लगभग तैयार है और समय–सारणी के अनुसार शुरू किए जाएंगे तथा रोल आउट का दूसरा चरण (फेज) अगस्त 2009 में शुरू करने की योजना है।

Hkk-ok-v-f'k-i- lo.j Qke! ¼vk;dMk dsæ½

भारतीय वानिकी अनुसंधान सूचना प्रणाली के उपयोग को शुरू करने के लिए एक टेण्डर प्रक्रिया के द्वारा भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई और यह सुविधा जुलाई 2009 तक स्थापित कर दी जाएगी। आई एफ आर आई एस उपयोग को शुरू करने के अलावा, भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म मेल और मैसेजिंग जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ अन्य संबद्ध सेवाएं शुरू करेगा।

eYVh&çkVksdky yscy fLofpx&opqvy çkbosV usVodZ

एम पी एल एस–वी पी एन के अधिष्ठापन से भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के विभिन्न भौगोलिक स्थानों, यथाः देहरादून में भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के साथ जोधपुर, जबलपुर, जोरहाट, कोयम्बटूर, बंगलूरू, रांची, शिमला, हैदराबाद, छिंदवाड़ा और इलाहाबाद में देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय संस्थानों एवं केंद्रों के साथ समर्पित संबंध बनाने में समर्थ हुआ है। व्यवस्था परिषद् के भीतर संरक्षित प्रेषण और सूचना को आपस में बांटने की सुविधा करती है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आई टी प्रभाग ने इंटरनेट पोर्टल शुरू किया है जिसमें उपभोक्ता व्यापक परिचालन की आवश्यकता वाले परिपत्रों, आदेशों को जारी कर सकता है। इस प्रयास ने उपभोक्ताओं की पहुंच को बढ़ाया और इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए कागज के उपयोग को भी घटाया है। एक एफ टी पी सर्वर स्थापित किया गया और इसका उपयोग परिषद् संस्थानों के बीच भारी मात्रा में अनुसंधान एवं प्रशासनिक आँकड़ों के सम्पादन एवं बांटने के लिए हो रहा है।

ohfM;ks dkWaÝsfUlax

इसके अलावा, इस नेटवर्क संयोजकता (एम पी एल एस–वी पी एन) को काम में लाने के लिए, वीडियो कांफ्रेन्सिंग सुविधा स्थापित की गई, जो परिषद् और संस्थानों में ई–गवर्नेन्स विकास के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। एक–एक से करीब 100 लोगों की भीड़ तक की रेंज के करीब 100 वीडियो कांफ्रेन्सिंग सत्रों की व्यवस्था की गई और एक साल के दौरान कार्यान्वित किया। इसमें भौगोलिक दूरी का ध्यान किए बिना वास्तविक समय में पारस्परिक संवाद के लिए शोधार्थियों एवं प्रशासकों की भागीदारी थी और मई 2008 से परिषद् के संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी की गई।

11 से 13 फरवरी 2009 तक सम्पन्न अनुसंधान नीति समिति की बैठक के दौरान आई सी टी के द्वारा प्रमुख उपयोगिता परिवर्धन किया गया, जिसमें परिषद् संस्थानों उदा.: शिमला, जबलपुर, जोरहाट, जोधपुर, कोयम्बटूर, बंगलूरू एवं रांची से वैज्ञानिकों की ज्यादा सहभागिता एवं भागीदारी वीडियो कांफ्रेन्सिग के जरिए सुनिश्चित की गई, जो पहले केवल संस्थान स्तर पर आर ए जी तक सीमित थी। इसने शोध प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार किया और पणधारियों की आवश्यकता को समझने में उन्हें समर्थ बनाया।

ई–गवर्नेन्स कार्यकलापों के अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्रशासन निदेशालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् मुख्यालय और इसके संस्थानों/केंद्रों में उपभोक्ताओं की सभी सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभाग के अन्य प्रमुख कार्यकलापों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- लान–वान सहायता
- हार्डवेयर की खरीद और रखरखाव
- नए प्रस्ताव
- प्रशिक्षण
- वीडियो कांफ्रेन्स, बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में तकनीकी प्रस्तुतिकरण के लिए आई टी सहायता उपलब्ध कराना।

yku&oku lgk;rk

- एम पी एल एस–वी पी एन उदा.– 11 एम पी एल एस लीज्ड लाइन और 2 MBPS 1:1 इंटरनेट बैण्डविडथ का नियमित रख रखाव/अनुवीक्षण।
- भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय और इसके संस्थानों में करीब 1100 उपभोक्ताओं के लिए ई–मेल, इंटरनेट आदि का नियमित रख रखाव और रिपोर्टिंग।
- भा.वा.अ.शि.प. की वर्तमान वेबसाइट (www.icfre.gov.in) एक सी एम एस आधारित वेबसाइट का अद्यतन।
- परिषद् मुख्यालय और संस्थानों के अपने उपभोक्ताओं में लगातार सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रॉक्सी सर्वर/वेब सर्वर का नियमित रख रखाव।
- एक केंद्रितकृत ए वी सर्वर के जरिए परिषद् मुख्यालय और व.अ.सं. परिसर में नेटवर्क एंटीवाइरस सुविधा का नियमित रख रखाव और रिपोर्टिंग।

gkMZos;j dh [kjhn vkj j[kj[kko

आई टी प्रभाग परिषद् मुख्यालय और व.अ.सं. में स्थापित कम्प्यूटर और बाह्य हार्डवेयर का रखरखाव करता हैं तदनुसार, इनके उपयुक्त रखरखाव और विक्रेताओं के साथ समन्वयन के लिए हार्डवेयर को श्रेणीकृत और सूचीकृत किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग उन विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा फोटोकॉपियर के लिए ए एम सी का प्रबंध भी करता है, जो अपने स्वयं की ब्राण्ड मशीनों मुख्यतः जीरॉक्स, एच सी एल और रीकोह की देखभाल करते हैं।

विभिन्न विक्रेताओं के जरिए परिषद् मुख्यालय के उपभोक्ताओं के लिए उपभोज्य की व्यवस्था करने हेतु उपभोज्य मदों और प्रिंटर कार्टेज के रेट कांट्रेक्ट भी प्रक्रमित एवं संचालित किए जाते हैं।

l=ikr

- पुराने हार्डवेयर (डेस्कटॉप, प्रिंटर और लैपटॉप्स) का उच्चीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
- तीसरे पक्ष विक्रेता के जरिए रखरखाव और सुविधा प्रबंध सेवा के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का परिषद् संस्थान वार रखरखाव समेकित किया जा रहा है।
- एक आई सी एफ आर ई वाइड सिंगल सेंट्रल एंटीवाइरस सृजित किया गया और एक केंद्रियकृत एंटीवाइरस परिषद् के संस्थानों में स्थापित किया गया।

çf'k{k.k

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् और इसके संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

lpuk çkS|kfxdh lgk;rk miyC/k djkuk

- प्रभाग ने परिषद् संस्थानों में वीडियो कान्फ्रेसिंग आयोजित करने में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग ने वर्ष 2007–08 में परिषद् मुख्यालय और वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित सभी बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में आई टी और दृश्य व्यवस्थाओं के संबंध में परिषद् मुख्यालय और व.अ.सं. को सहायता उपलब्ध कराई।

çdk'ku

श्री जगदीश किशवान और अनीता श्रीवास्तव (2008): ''रोल ऑफ फॉरेस्ट इन डिजास्टर मिटिगेशन''। यह शोध पत्र 21 से 24 अक्टूबर 2008 तक एन ए सी हैदराबाद में सम्पन्न आपदा प्रबंधन पर पहले विश्व कांग्रेस–2008 में प्रस्तुत किया गया।

डॉ. रेनू सिंह अैर अनीता श्रीवास्तव (2008): ''की मैनेजमेण्ट इशूज ऑफ फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पीसिज इन इंडिया'' यह शोध पत्र वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में 1 से 3 दिसम्बर 2008 तक सम्पन्न जैवविविधता प्रबंध और मानव कल्याण में वर्गिकी की भूमिका पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान प्रस्तुत किया गया।

श्री जगदीश किशवान और वी.आर.एस.रावत (2008): फॉरेस्ट कन्जरवेशन बेस्ट क्लाइमेट चेन्ज–मिटिगेशन एप्रोच फॉर इंडिया। इन्टरनेशनल फॉरेस्ट्री रिव्यू, वॉल्यू. 10(2), 269–280।

डॉ. रेनू सिंह और वी आर एस रावत (2008): अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही– डेवलपमेंट मैथोडोलॉजी फॉर एसैसमेन्ट ऑफ इनहैन्समैन्ट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स ड्यू टू कन्जरवेशन. सस्टेनेबल मैनेजमेन्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्क्रीज इन फॉरेस्ट कवर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून द्वारा 7 और 8 मार्च 2008 को नई दिल्ली में आयोजित ।

डॉ. रेनू सिंह एवं वी. आर. एस. रावत (2008) : राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही– फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इन इंडिया : स्टेकहोल्डर्स डायलॉग एंड कैपिसिटी बील्डिंग, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून द्वारा 21 और 22 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित।

डॉ. रेनू सिंह, अनीता श्रीवास्तव और ओम कुमार (2009), इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लान्ट बायोडाइवर्सिटी। बुल. एन्वा. साइंस. वॉल्यू 15, पी पी 137–142।

ikLVj çLrqfrdj.k

अनीता श्रीवास्तव एवं ओम कुमार (2008) : ''इम्पोर्टेन्ट फ्लोरल स्पीसिज इन मण्डल चोप्ता फॉर ह्यूमन वैल्फेयर'' पोस्टर वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में 1 से 3 दिसम्बर 2008 तक जैवविविधता प्रबंध और मानव कल्याण में वर्गिकी की भूमिका पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान प्रदर्शित किया गया।